Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 9.134
Volume - 9, Issue - 6, June - 2026

DOIs:10.2018/SS/202606021 --:-- Research Paper / Article / Review

उत्तर प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति : एक विश्लेषण

डॉ. देवेन्द्र कुमार
सह-आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान विभाग / पुस्तकालय विभाग
राजकीय महिला महाविद्यालय, खरखौदा, मेरठ (उ0प्र0)
ई-मेल आई.डी. : dkdeobhu@gmail.com

सारांश: प्रस्तुत लेख में उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया गया हैं। लेख में राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों की वर्तमान मानव संसाधन, पुस्तकालय का स्थान, पुस्तकालय संग्रह विकास नीति, पुस्तक क्रय प्रक्रिया, डिजिटल और ई—संसाधनों की स्थिति, पारंपरिक संसाधनों, मुद्रित, एवं सन्दर्भ संग्रह, पुरानी / अप्रयोज्य सामग्री हटाने सम्बन्धी नीति का अभाव, बजट की कमी, डिजिटल संसाधन और ई—लाइब्रेरी, ई—लर्निंग पार्क और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, डेलनेट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ़ इंडिया, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल, और पुस्तकालय ऑटोमेशन का सारगर्भित सम्यक विश्लेषण किया गया है। अंत में सभी तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष और सुझाव दिया गया है।

बीजशब्द : राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालय, पुस्तकालय मानव संसाधन, पुस्तकालय संग्रह विकास नीति, डिजिटल व ई—संसाधन, ई—लर्निंग पार्क।

"पुस्तकालय विचारों का जन्मस्थान है—एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास जीवंत हो उठता है।" – (नॉर्मन कजिन्स)

1. परिचय

उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के कारण उच्च शिक्षा के एक विशाल संरचना को संभालता है। उत्तर प्रदेश में कई हजार महाविद्यालय (राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और निजी महाविद्यालय मिलाकर) संचालित हैं। इन महाविद्यालयों के सुव्यवस्थित संचालन और अकादमिक गुणवत्ता को बनाए रखने में पुस्तकालय की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान होती है। किसी भी शैक्षणिक संस्था में पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र होता है। यह मात्र पुस्तकों का संग्रह नहीं, अपितु एक ऐसा स्थान है जहाँ नवीन ज्ञान एवं विचारों को बढ़ावा मिलता है। महाविद्यालय की शिक्षा और महाविद्यालय पुस्तकालय का आपस में सम्बन्ध अत्यंत ही गहनता से जुड़े हुए हैं। पुस्तकालय छात्र—छात्राओं को ज्ञान अर्जित करने, मूल्यांकन करने और समझने के लिए प्रोत्साहित करती है, साथ ही उन्हें आगे के अध्ययन हेतु नई दिशा और विषयों से भी परिचित कराती है। पुस्तकालय मुख्य रूप से महाविद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने, ज्ञान का संग्रह करने, एवं संस्थान के बौद्धिक केंद्र के रूप में काम करता है।

महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को वाँछित ज्ञान स्रोत सामग्री खोजने और उसकी अनुशंसा करने में सहायता करते हैं, साथ ही यह भी निर्धारित करने में सहायता करता है कि उन्हें किस प्रकार के सामग्री की आवश्यकता है। पुस्तकालयाध्यक्ष पाठकों को बुनियादी कंप्यूटर कौशल सिखाते हैं, उन्हें नीतियों और पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग के सम्बन्ध में शिक्षित करते हैं। पुस्तकालयों में नवीन तकनीक का उपयोग करने और सूचना को समझने के तरीके पर भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष को मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक सूचना स्रोतों और डेटाबेस दोनों का ज्ञान होना चाहिए। महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष को पाठकों की आवश्यकताओं को शीघ्रता से और सटीकता से पहचानने में सक्षम होना चाहिए। कर्मचारी, पाठ्य सामग्री और उपयोगकर्ता एक पुस्तकालय की मूलभूत त्रिमूर्ति हैं। एक पुस्तकालय की सफलता विशेषकर उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो उपयोगकर्ताओं के हाथों में पाठ्यसामग्री के अच्छे संग्रह के प्रभावी उपयोग के लिए उत्तरदायी हैं। उत्कृष्ट पाठ्यसामग्री संग्रह वाला पुस्तकालय कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों के बिना अपने उपयोगकर्ताओं को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है। इस प्रकार किसी भी पुस्तकालय के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ईमानदार और संगठित मानवीय प्रयास आवश्यक है। पुस्तकालय

कर्मचारियों का मूल उद्देश्य "सही सूचना या पाठ्य सामग्री सही पाठक तक, सही समय पर और सही तरीके से पहुँचाना होना चाहिए"। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाठ्यसामग्री के चयन या उनसे ज्ञान प्राप्त करने में सहायता की आवश्यकता मांगने वाले किसी भी पाठक को यथोचित सहायता अवश्य मिले।

2. महाविद्यालय पुस्तकालय के कार्य

पुस्तकालय महाविद्यालय का अभिन्न अंग हैं। प्रख्यात शिक्षाविद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, "पुस्तकालय किसी भी शैक्षणिक संस्थान का वास्तविक हृदय होता है"। वे पुस्तकालयों को ज्ञान का ऐसा जीवंत केंद्र मानते थे जो छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करता है। पुस्तकालय का मुख्य कार्य शिक्षितों को शिक्षित करना है। एक सुसज्जित पुस्तकालय न केवल ज्ञान और अनुभव का भंडार है, बल्कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक विश्व संस्कृति का संग्रह के साथ—साथ वाहक भी है। महाविद्यालय पुस्तकालय महाविद्यालय के शिक्षण कार्यक्रम को समर्थन देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक है।

महाविद्यालय पुस्तकालय के कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है :-

- शिक्षण और अनुसंधान के लिए आवश्यक सूचना संसाधन उपलब्ध कराना।
- शिक्षक को अपने क्षेत्र में नवीनतम विकास से अवगत रहने में सहायता करना।
- सभी औपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करना।
- छात्र—छात्राओं हेतु विशाल ज्ञान जगत के द्वार खोलना, जो शिक्षक के विशेषज्ञता क्षेत्र की सीमाओं से परे है, और
- छात्र—छात्राओं और शिक्षकों को ऐसे शैक्षणिक वातावरण में एक साथ लाना जो आनंददायक पठन, आत्म-खोज, व्यक्तिगत विकास और बौद्धिक जिज्ञासा को प्रवर्धित करने को प्रोत्साहित करता है।

3. उत्तर प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति का सम्यक मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है :-

3.1. राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों में मानव संसाधन

मानव संसाधन प्रबंधन (Human Resource Management) लोगों के आयाम से संबंधित है, क्योंकि प्रत्येक संगठन मानव संसाधन से बना होता है। मानव संसाधन सेवाएं प्राप्त करना, उनके कौशल का विकास करना, उन्हें उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना और यह सुनिश्चित करना कि वे संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें, संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अकादमिक पुस्तकालयों में मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रियाएं जो मानव संसाधनों की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और सभी संगठनात्मक लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध और कार्यान्वित की जाती हैं, के रूप में परिभाषित किया गया है।

वर्त्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 240 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। जिनमे से कुल 23 राजकीय महाविद्यालय विभिन्न राज्य विश्वविद्यालय प्रशासन के अन्तर्गत संघटक महाविद्यालय के रूप में संचालित हैं अर्थात कुल 217 राजकीय महाविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत वर्तमान में गतिमान हैं। 240 राजकीय महाविद्यालयों में से 02 राजकीय महाविद्यालयों का शैक्षिक सत्र 2025—26 तक निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण संचालन नहीं हो पाया है। अर्थात कुल 238 राजकीय महाविद्यालय वर्तमान में संचालित हैं। 240 राजकीय महाविद्यालय में से कुल 21 राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता—पुस्तकालय (पूर्व नाम पुस्तकालयाध्यक्ष) का पद सृजित नहीं हैं और मात्र कुल 219 राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता—पुस्तकालय के पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष वर्तमान में मात्र 32 प्रवक्ता—पुस्तकालय ही कार्यरत है। साथ ही सभी महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानक अनुरूप अन्य पुस्तकालय कार्मिकों का नितांत अभाव है जिस कारण वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली रूप से पुस्तकालयों सेवाएं प्रदान करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मानव संपदा संसाधन अभाव के कारण प्रभावशाली रूप में पुस्तकालय सेवाओं को प्रदान करने में निरंतर समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिस पर शासन द्वारा सम्यक विचार कर आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रवक्ता—पुस्तकालय की कमी के कारण प्रायः महाविद्यालय के किसी प्रवक्ता या लिपिक को पुस्तकालय के संचालन का अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है, जो पुस्तकालय सेवाओं एवं तकनीकी से प्रशिक्षित नहीं होने के कारण प्रभावशाली सेवाओं को वैज्ञानिक तरीके से नहीं प्रदान कर पाते है। इसका परिणाम यह होता है कि पुस्तकालय की उपयोगिता में बाधाएँ आती हैं और छात्रों तथा शिक्षकों की शैक्षणिक प्रगति के लिए आवश्यक प्रभावशाली पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करने और पाने में अवरोध उत्पन्न होता है।

3.2. राजकीय महाविद्यालय में पुस्तकालय का स्थान

विश्लेषण में यह पाया गया है कि कई राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयों के पास पर्याप्त स्थान नहीं है। जिससे छात्रों के बैठने की क्षमता की समस्या रहती है। अधिकतर राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय सामान्यतः एक कमरे में ही संचालित किया जा

रहा है जिससे कार्य करने एवं सेवाओं को प्रदान करने में समस्या बनी रहती है। कई राजकीय महाविद्यालयों में मानक के अनुरूप न तो पुस्तकालय भवन है और न ही सुविधाजनक वाचनालय है।

4. पुस्तकालय संग्रह विकास नीति

उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों में संग्रह विकास नीति की स्थिति अव्यवस्थित और अनियमित है। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रहे अधिकतर राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्य सामग्री संग्रह विकसित करने के लिए कोई लिखित नीति नहीं है। जिस कारणवश पुस्तकालय का कामकाज और पाठ्य सामग्री क्रय करना, उच्च शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के सामान्य दिशा—निर्देशों पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश में राजकीय महाविद्यालययों के पुस्तकालयों में संग्रह विकास के वास्तविक स्थिति का विवरण निम्नलिखित है :-

- **लिखित संग्रह विकास नीति का अभाव**: अधिकतर राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालय में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कोई औपचारिक, लिखित संग्रह विकास नीति नहीं है । संग्रह विकास नीति मुख्य रूप से पाठ्यक्रम और उपलब्ध बजट पर आधारित होता है।

- **पुस्तक क्रय प्रक्रिया**: पुस्तकालय में पुस्तकें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों (जैसे उत्तर प्रदेश वित्तीय नियमावली) के अनुसार क्रय की जाती हैं। पुस्तकालय समिति विभिन्न विभागों से किताबों की मांग सूची इकट्ठा करती है और क्रय केवल राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध प्रकाशकों / विक्रेताओं से की जाती है ।

- **डिजिटल और ई—संसाधनों की स्थिति**: अधिकतर राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालय में ई—संसाधनों (जैसे ई—जर्नल, डेटाबेस) के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं है। हालाँकि राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में स्वतंत्र ई—संग्रह नीति का न होना वर्तमान में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ONOS और NDLI जैसे राष्ट्रीय कन्सोर्शिया के माध्यम से ई—जर्नल्स और डेटाबेस तक पहुँच आसान हो गई है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल्स के माध्यम से भी डिजिटल अध्ययन सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है, परन्तु वर्तमान में कोई स्वतंत्र ई—संग्रह नीति नहीं है।

- **पारंपरिक संसाधनों पर बल**: उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों में संग्रह मुख्य रूप से पारंपरिक मुद्रित किताबों और पत्रिकाओं तक ही सीमित हैं। संग्रह में ऐसी पाठ्यपुस्तकों की प्रधानता है जो छात्रों की परीक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जबकि शोध—स्तर की किताबों और संदर्भ ग्रंथों का अनुपात अपेक्षाकृत कम है।

- **मुद्रित, एवं सन्दर्भ संग्रह**: ज़्यादातर राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अनुरूप पर्याप्त संख्या में पाठ्य पुस्तकें और सन्दर्भ ग्रंथों का अभाव है। जो पाठ्य सामग्री है भी उनमे ज्यादातर पाठ्य सामग्री सामान्यतः लगभग विगत 10 वर्ष से अधिक पुरानी हैं जिससे अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को अध्ययन हेतु पर्याप्त पाठ्य सामग्री नहीं प्राप्त हो पा रहा है।

- **पुरानी/अप्रयोज्य सामग्री हटाने (Weeding Out) नीति का अभाव**: कई राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों में पुरानी, अनुपयोगी या क्षतिग्रस्त पुस्तकों / पाठ्य सामग्रियों को हटाने के लिए कोई स्पष्ट नियमित नीति नहीं है। इससे महाविद्यालय पुस्तकालयों में स्थान का अभाव होता जा रहा है।

- **बजट की कमी**: पर्याप्त और समय पर वित्तीय आवंटन न होने से संतुलित और अद्यतन संग्रह बनाने में बाधा उत्पन्न होता है।

- **मानक क्रय नीति का अभाव**: पाठ्य सामग्रियों का क्रय सामान्यतया प्रशासनिक स्तर पर की जाती है, जिसमें महाविद्यालय पुस्तकालय प्रभारी की भूमिका समस्त प्रक्रिया में मात्र नियमानुसार सहयोग करने की होती है। उक्त प्रक्रिया का कोई मानक निश्चित नहीं किया गया है जिससे यह नीति सामान्यतः आवश्यकता आधारित ही बनकर रह गई है ।

5. डिजिटल संसाधन और ई—लाइब्रेरी

उत्तर प्रदेश डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल ई—लर्निंग हेतु संसाधनों का एक डिजिटल भंडार है। यह न केवल सर्च सुविधाओं वाला एक संसाधन ही नहीं है अपितु उच्च शिक्षा के क्षेत्र हेतु विभिन्न प्रकार की सेवाएँ भी देता है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित और निर्देशित किया जाता है। इसे सभी विषयों और लोकप्रिय अभिगम उपकरण पर उच्च शैक्षणिक स्तरों—जिनमें शोधकर्ता, स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र—छात्राएं सम्मिलित हैं—को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पोर्टल पर

पाठ्यपुस्तकें, लेख, वीडियो, ऑडियो फ़ाइलें, और सीखने की अन्य सामग्री उपलब्ध है। यह कई भाषाओं में शैक्षिक सामग्री तक मुफ़्त पहुँच प्रदान करता है। यह पोर्टल 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस के अवसर पर आरम्भ किया गया था। वर्तमान में इस पोर्टल के माध्यम से राज्य भर में सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही सहायता प्राप्त हो रही है, क्योंकि कई विद्वानों ने पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य सामग्री पोर्टल पर अपलोड की है, जो समस्त के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।

डिजिटल संसाधन और ई—लाइब्रेरी के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं संचालित हैं :-

ई—लाइब्रेरी

उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में ई—लाइब्रेरी स्थापित की गई है जिसके माध्यम से ऑनलाइन सर्विसेज एवं ई-रिसोर्सेज समस्त को निशुल्क प्रदान की जा रही है। उक्त हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि का प्रावधान किया जाता है जिसके माध्यम से आवश्यक सामग्रियों का क्रय किया जा सकता है ।

ई—लर्निंग पार्क और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 शिक्षा में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विशेष बल देती है। उत्तर प्रदेश के कई राजकीय महाविद्यालय पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं। सरकार इन महाविद्यालयों में ई—लर्निंग पार्क, वाई—फ़ाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी ज़रूरी सुविधाएँ देकर विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के छात्रों को सभी ज़रूरी शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ई—लर्निंग पार्कों में डिजिटल लाइब्रेरी के साथ—साथ कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और वाई—फ़ाई जैसी सुविधाएँ भी प्रदत्त की जाती है। उच्च शिक्षा विभाग की रिपोर्ट है कि इनमें से ज़्यादातर ई-पार्क पहले से ही चालू हैं और कुछ तो महाविद्यालयों समय के बाद भी काम करते रहते हैं। ई—लर्निंग पार्कों के अतिरिक्त, राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों में विशेषरूप से दूर—दराज़ के क्षेत्रों, तहसील मुख्यालयों और ब्लॉक मुख्यालयों में डिजिटल कंटेंट वाले ई—टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। विषय विशेषज्ञ, शिक्षक और अन्य लोग इन ई—टैबलेट पर ई—कंटेंट अपलोड और डाउनलोड करते हैं, जिससे छात्रों को पढ़ने के लिए सुविधाजनक और प्रभावी तथा गुणकारी सामग्री मिलती है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र—छात्राएं अपना शैक्षणिक विकास करते हुए देश के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल

राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अन्तर्गत राज्य के लगभग 72 विश्वविद्यालयों (राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों) और उनसे सम्बद्ध सैकड़ों महाविद्यालयों को एक मंच पर लाया गया है। इस पोर्टल पर 88256 से अधिक ई—कंटेंट (वीडियो, ऑडियो, ई—बुक्स, पीपीटी) मुफ्त उपलब्ध हैं। इससे छात्र—छात्राएं और शिक्षक मोबाइल फोन और कंप्यूटर से हज़ारों ई-बुक और इंटरनेशनल ई—जर्नल ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में लर्निंग रिसोर्स कलेक्शन की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पारंपरिक किताबों के साथ—साथ डिजिटल संसाधन (जैसे ई—लाइब्रेरी और ऑनलाइन जर्नल) को शामिल करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS)

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के आधुनिकीकरण अभियान के अन्तर्गत महाविद्यालयों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में ONOS सेवा पूरी तरह से लागू कर दी गई है। इसके अन्तर्गत राज्य के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों के 13000 से अधिक ई—जर्नल और शोध पत्रिकाओं तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जा रही है। राजकीय महाविद्यालय नेटवर्क के बाहर भी ऑनलाइन सदस्ता के माध्यम से लॉग—इन करके अकादमिक संसाधन का निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक महत्वपूर्ण सेवा है किन्तु राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं अध्ययनरत छात्रों के पाठ्यक्रमानुसार अद्यतन बहुत उपयोगी नहीं हैं, क्योंकि कई प्रसिद्द एकेडमिक जर्नल पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं और जो उपलब्ध हैं वे अधिकतर शिक्षकों एवं शोध छात्रों के शोध अनुरूप आवश्यकता को पूर्ण नहीं करते हैं। अनुसंधान और उन्नत अध्ययन में मदद के लिए डेलनेट और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ़ इंडिया की सदस्यता भी ली जा रही है।

पुस्तकालय ऑटोमेशन (Library Automation)

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कई राजकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान एवं प्रधानमंत्री उच्चत्तर शिक्षा अभियान के अंतर्गत पुस्तकालय ऑटोमेशन का कार्य किया गया है एवं अद्यतन शेष महाविद्यालयों में पुस्तकालय ऑटोमेशन का कार्य गतिमान

है। ऑटोमेशन होने से पुस्तकालय कार्यों में गतिशीलता आएगी और समस्त महाविद्यालय शैक्षणिक सेवाओं में सहायता प्राप्त होगी। उक्त कार्य को निरन्तर संचालित करने एवं छात्र—छात्राओं की सदस्ता हेतु स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए कोई वित्तीय सहायता नियमानुसार उपलब्ध नहीं है जिससे लाइब्रेरी ऑटोमेशन का उद्देश्य अधूरा है।

महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए वित्तीय सहायता

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों में विभिन्न सेवाएं एवं क्रियाकलाप संचालित की जा रही हैं, किन्तु पुस्तकालयों में नए पाठ्यक्रम एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावशाली रूप से संचालित करने हेतु किसी भी प्रकार के वित्तीय अनुदान एवं नियमों को प्रदान करने सम्बन्धी स्पष्ट नीति का पूर्ण अभाव है, जिसका प्रभाव महाविद्यालय के सम्पूर्ण शैक्षणिक वातावरण एवं उन्नति पर पड़ता है।

6. निष्कर्ष और सुझाव

उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों का विश्लेषण करने के उपरांत यह प्राप्त होता है कि अधिकांश राजकीय महाविद्यालयों में पूर्ण रूप से प्रवक्ता-पुस्तकालय कार्यरत नहीं हैं। साथ ही अधिकांश राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता अनुरूप और राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पाठ्यसामग्री एवं सेवाओं का नितांत अभाव है। सबसे पहले महाविद्यालयों में योग्य और स्थायी पुस्तकालय कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य है। किसी भी महाविद्यालय पुस्तकालय की सफलता मुख्य रूप से उसके बौद्धिक, भौतिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती है जिससे कि पुस्तकालय प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर सके। पुस्तकालय को प्रभावशाली और उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि पुस्तकालय उत्कृष्ट पुस्तकालय और सूचना सेवाएँ अपने सदस्यों को आवश्यक होने पर तत्काल प्रदान करे जिससे कि समस्त सदस्यों की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सके। महाविद्यालय पुस्तकालय में पर्याप्त जगह, अप—टू—डेट जानकारी वाली सामग्री का संग्रह, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय सामग्री का संग्रह, सूचना और संचार तकनीक की सुविधाएँ और निरंतर पर्याप्त बजट होना चाहिए। साथ ही सरकारी मदद के अतिरिक्त एक शैक्षणिक संस्थान के तौर पर महाविद्यालय को सीमित संसाधनों के भीतर पुस्तकालयों के विकास हेतु एक व्यावहारिक नीति बनानी और लागू करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालय में पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में अनेक ई—सेवाओं को लागू किया गया है जिसके सफ़ल संचालन हेतु प्रवक्ता—पुस्तकालय के सहायतार्थ अन्य प्रशिक्षित कार्मिकों की तत्काल नियुक्ति अपरिहार्य है।

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग को उपरोक्त समस्याओं पर तत्काल विचार करते हुए राजकीय पुस्तकालय के संग्रह विकास, सेवाओं, वित्तीय सहायता एवं अन्य आवश्यकताओं पर समस्त राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालयों हेतु एक समान पुस्तकालय प्रणाली और संग्रह विकास नीति तैयार किया जाना चाहिए जिससे की प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को सफल बनाने में राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालय अपना प्रभावशाली योगदान प्रदान कर सके।

सन्दर्भ स्रोत :

1. Asif & Singh, K. K. (2022). Libraries @ national education policy (NEP 2020) in India. *IP Indian Journal of Library Science and Information Technology*, 7(1), 18–21.
2. Biswajit Das (2025). Analytical study on National Education Policy 2020 of Library & Information Sciences (LIS) Education. *International Journal of Research*, 11(1), 103-112.
3. Das, P. & Biswas, G. (2024 (2024). National educational policy 2020: changing role and status of the college libraries in the higher education sector of India. Proceeding in National Conference on Multi-Disciplinary Research (NCMR 2024), during February 28-29, 109-115.
4. Devendra Kumar (2025). E-learning Park: A new vision for government degree colleges of Uttar Pradesh. In: Arolkar, D. B. & Hugar, Jayprakash G. (2025). AI-Driven Libraries : Shaping the Future of Knowledge Management. Panaji, Goa: Qurate Books Pvt. Ltd., 216-223.
5. Devendra Kumar, Abdul Quadir & Siddiqui, JA (2017). Human Resource Management in Government College Libraries: A Study of Uttar Pradesh. *Indian Journal of Information Sources and Services*, 7(2), 9-17.
6. Dhimal A. K, Sinha S. C. (2002), Academic Libraries, Ess Publications, New Delhi.
7. Frempong-Kore, Afua (2021). The Relevance of Collection Development Policy in the Collection Development of Maranatha University College and Ghana Christian University College Libraries. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, 1-27.

8. Giri, Rabishankar, Sen, B. K. & Mahesh, G. (2015). Collection Development in Indian Academic Libraries: An Empirical Approach to Determine the Number of Copies for Acquisition. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology,* 35(3), 184-192.
9. Gosavi, Nandkishor Balu (2021). Collection of E-Resources in Libraries: A Review. *International Research Journal of Humanities and Interdisciplinary Studies (IRJHIS)*, 2(8), 47-53.
10. Govt. of India, Ministry of Human Resource Development. (2020). National Education Policy 2020. Government of India.
11. Khan, Alamgir & Munshi, Shamim Aktar, Ed. (2022). Library management during pandemic : issues and challenges. New Delhi: Ess Ess Publications.
12. Roy, B. Kumar, Biswas, and Subal Chandra (2022). Collection Development and Organization in Institutional Digital Repositories: From Policy to Practice. *International Journal of Information Science and Management*, 20(1), 15-39.
13. Yadav, Hemant Singh & Dubey, Pradeep Kumar (2020). महाविद्यालयों में पुस्तकालय सेवाओं की स्थिति का मूल्यांकन. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, 17(2), 1094-1100.
14. कुमार, ए. (2018). भारत में शैक्षणिक पुस्तकालय प्रबंधनः चुनौतियाँ और अवसर। नई दिल्लीः अटलांटिक प्रकाशक।
15. कुमार, ए. और शर्मा, पी. (2020). उच्च शिक्षा में डिजिटल पुस्तकालय सेवाएं : एक विश्लेषण. *भारतीय शैक्षणिक शोध पत्रिका,* 45(3), 123-130.